SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

बिहार के आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका: 2000 से वर्तमान तक

जितेन्द्र प्रसाद, पीएच–डी., अर्थशास्त्र विभाग
ब्रजमोहन दास महाविद्यालय, दयालपुर, वैशाली, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
जितेन्द्र प्रसाद, पीएच–डी.
E-mail : prasadjitendar589@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 08/04/2025
Revised on : 07/06/2025
Accepted on : 17/06/2025
Overall Similarity : 01% on 09/06/2025

शोध सार

बिहार आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से विकासशील राज्यों की श्रेणी में आता है जहां पर सामाजिक स्तर पर गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन एवं वर्ग भेदभाव जैसी समस्या एक तरफ दिखाई देती है तो वही पर दूसरी तरफ हाल के वर्षो में विकास की अन्य नीतियाँ सराहनीय कही जा सकती हैं। इस विषय पर सामाजिक वैज्ञानिको के बीच मतभेद रहा है जिसको की इस शोध पत्र के माध्यम से बिहार राज्य के तरफ से किये गए आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए अनेक प्रयासों पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। हाल के वर्षो में बिहार राज्य में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा गया है जिसमे इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP), अवसंरचना में प्रगति, शहरी विकास, कृषि सुधार, औद्योगिक निवेश, महिला सशक्तिकरण और क्षेत्रीय सुधारों के सम्बन्ध पर विशेष चर्चा की गई है। नीतीश कुमार की नई सरकार ने बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनेक काम किया है जिसमें की एनडीए सरकार ने अनेक क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण और समर्थन जुटाया है। यह शोध पत्र इन्ही आर्थिक नीतियों पर विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द

बिहार, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, महिला सशक्तिकरण.

परिचय

बिहार राजनीतिक– आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है जबकि भारत के विकासशील आर्थिक नीतियों में अन्य राज्यों की अपेक्षा सामाजिक स्तर पर गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन तथा अन्य सामाजिक कुरीतियाँ और वर्ग भेदभाव बिहार में व्याप्त रहा है। राज्य

के तरफ से बिहार में आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए अनेक प्रयत्न किये गए है, जिसमें कि सरकारी आर्थिक नीतियाँ सराहनीय रही है। हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा गया है, जिसमें इसकी सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP), अवसंरचना में प्रगति और क्षेत्रीय सुधारों में भारी वृद्धि हुई है।

बिहार में आर्थिक विकास एक समस्या के तौर पर देखा गया है जहाँ पर आधुनिकता का द्वंद भी देखा जा सकता है जो की एक जटिल सैद्धांतिक समस्या के रूप में है। एक तरफ नए बाजार, चौड़ी सड़क, फ्लाईओवर, हॉस्पिटल्स, शिक्षा में सुधार, इत्यादि दिखता हैं, वही पर पलायन, बेरोजगारी, वर्ग भेदभाव तथा आर्थिक असमानताएं समाज का मुख्य हिस्सा रही है जिसे नकारा नहीं जा सकता है।

विकास और वित्तीय स्थिरता

2011–12 से 2023–24 के बीच, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्तमान मूल्यों पर 2.47 लाख करोड़ से बढ़कर 8.54 लाख करोड़ हो गया है, जो कि लगभग 3.5 गुना वृद्धि दर्शाता है। कर राजस्व सबसे मुख्य आय का स्रोत बन गया है, जो 2023–24 में कुल प्राप्तियों का 83.8 प्रतिशत था, जबकि 2019–20 में यह 75.3 प्रतिशत था। परिवहन और संचार क्षेत्र ने 2011–24 के दौरान 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की, जिससे बिहार इस क्षेत्र में शीर्ष तीन राज्यों में शामिल हो गया है।[1]

2002 से 2007 तक बिहार राज्य का लगभग उत्पादन 0.38 प्रतिशत रहा था, जबकि 2021–22 में उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि 3.9 प्रतिशत का रहा है, जो की उत्पादन में सुधार को प्रदर्शित करता हैं। 2005 के बाद नितीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने अनेक आर्थिक और सामाजिक सुधार को लेकर नीतियों को कार्यान्वित किया है। 2010 में भारतीय सरकार के CSO (Central Statistics Organisation) के सर्वे में रिपोर्ट जारी किया की पांच वर्षो में 2004–5 और 2008–9, GDP 11.3 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई थी जिसमें की बिहार भारत में दूसरा सबसे ज्यादा आर्थिक बढ़ोतरी वाला राज्य रहा था।[2]

शहरी विकास

बिहार ने कनेक्टिविटी और शहरी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक आधारभूत ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं। राज्य ने लगभग 50,000 करोड़ की लागत वाली 430 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है, जो जून से अगस्त 2025 के मध्य आरंभ होंगी।

विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार पटना व्यापार के शुरुआत के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है।[3] 20 मई 2025 को मुख्यमंत्री ने सभी 38 जिलों में सड़कों, जल निकासी प्रणालियों, पार्कों और घाटों को बेहतर बनाने हेतु कुल 1,002 करोड़ की लागत वाली 1,327 शहरी आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

बिदुपुर पुल, गंगा नदी पर बन रहा है, यह छह लेन पुल अपने पूर्णता के करीब है, जो पटना को वैशाली जिले से जोड़ेगा और उत्तर–दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। पटना में गंगा नदी के किनारे 20.5 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे शहरी गतिशीलता और सौंदर्य को बढ़ाएगा।

औद्योगिक विकास और निवेश

बिहार ने औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किए हैं, इसमें सितंबर 2024 तक, राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड को 3,752 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनका कुल मूल्य 75,293.76 करोड़ है। सूक्ष्म और बड़े उद्यमों में निवेश में 135 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि बड़े पैमाने पर इकाइयों में 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसने भारी रोजगार सृजन को जन्म दिया।

राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न नीतियां शुरू की हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। सरकार निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जैसे लघु मशीन विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, आईटी, विद्युत हार्डवेयर विनिर्माण, प्लास्टिक, रबर और चमड़ा आदि। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाता है। आर्थिक सर्वेक्षण के एक आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बिहार में सबसे बड़ा है।[4]

बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) का उद्देश्य राज्य की कामकाजी आबादी की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना है। बीएसडीएम का प्राथमिक ध्यान रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि प्रदान करना है। इसकी स्थापना के बाद से 20 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है और पूरे राज्य में प्रशिक्षण केंद्रों का नेटवर्क अच्छी तरह से स्थापित है। नई पहल के हिस्से के रूप में बीएसडीएम ने पटना नगर निगम के साथ साझेदारी में विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त बीएसडीएम ने राज्य के अनौपचारिक क्षेत्रों में स्ट्रीट फूड वेंडर रिटेलर सहित कौशल विकास के लिए नए रास्ते खोले हैं और उन्हें उनके कौशल के लिए मूल्यवान मान्यता प्रदान की है।

कौशल युवा कार्यक्रम (KYP) 1886 केंद्रों से संचालित एक कार्यक्रम है, जिसमें 2023–24 में 4.7 लाख से अधिक प्रशिक्षण शामिल हैं। इसमें लिंग अनुपात में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी में भारी वृद्धि हुई है। उद्योग मित्र बिहार में व्यवसाय करने की आयु सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। उद्योग मित्र अन्य सेवाओं के अलावा परियोजना प्रोफाइल पर सलाह देकर बिहार में उद्योग स्थापित करने में नए उद्यमियों की सहायता करते हैं। इसके अलावा यह राज्य सरकार के विभिन्न कार्यों के लिए धन और पूरी आबादी के लिए आवंटन का समर्थन करने के लिए सेमिनार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

कृषि क्षेत्र

बिना समृद्ध कृषि क्षेत्र के किसी भी समाज की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती हैं। लगभग 75 प्रतिशत बिहार की जनसंख्या का मुख्या आय स्रोत कृषि ही है। सरकार ने चौथा कृषि रोडमैप तैयार (2023–28) किया है जिससे की फसलों से होने वाले उत्पादन को बढ़ाया जा सके। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत सरकार ने 13 जिलों में 20000 एकड़ भूमि का वितरण किसानो को किया है।[5]

2022–23 से 2023–24 के बीच, चावल और गेहूं के उत्पादन में क्रमशः 21 प्रतिशत और 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आम के उत्पादन में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और लीची बाग क्षेत्र में 6 प्रतिशत का विस्तार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लीची के उत्पादन में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है। इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पीएसीएस) के माध्यम से नए अनाज भंडारण गोदामों का निर्माण मंजूर किया।

बिहार में बागवानी का विकास बढ़ रहा है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को अपनाने से किसानों को बिहार में फल और सब्जी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केले के बाद सबसे महत्वपूर्ण फल आम है। 2022–23 और 2023–24 में आम की वृद्धि केवल 1.0 प्रतिशत थी लेकिन उसके बाद इसका उत्पादन 9.7 प्रतिशत बढ़ गया है।

बिहार में एक और उच्च मूल्य वाला फल मखाना है। 2023–24 में 27.8 हजार हेक्टेयर भूमि पर मखाना की खेती की गई और कुल उत्पादन 56.4 हजार टन था। भारत में कुल मखाना उत्पादन का 85 प्रतिशत हिस्सा बिहार का है।[6]

यह सर्वविदित है कि मखाना उत्पादन में बिहार का एक प्रमुख निर्यात उत्पाद बनने की क्षमता है। उम्मीद है कि मखाना का कुल निर्यात 200 टन तक बढ़ सकता है और इसका अनुमानित मूल्य लगभग 600 से 800 करोड़ रुपये है। आम, मखाना और लीची जैसे उत्पादों ने बिहार के बाहर भी अच्छा बाजार बनाया है। हाल के वर्षों में बागवानी के लिए राज्य सरकार का समर्थन काफी बढ़ गया है।

निदेशालय ने तीन घटकों के माध्यम से मखाना विकास योजना को क्रियान्वित किया है। पहला, राज्य सरकार भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया और राष्ट्रीय मखाना केंद्र, दरभंगा को उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों के प्रजनन के लिए सहायता प्रदान करती है, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण किस्मों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए सरकार ने मखाना किसानों को 75 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म

खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के तहत मखाना को एक जिला एक उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया है। इस योजना से मखाना उत्पादकों को विभिन्न प्रकार से लाभ मिलेगा।

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं को सशक्त करने और सामाजिक कल्याण में सुधार के प्रयास कई में योजनाओं का सृजन सरकार के द्वारा किया गया हैं जैसे कि,

- जीविका निधि योजना के तहत महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी बैंक की स्थापना के लिए 1,000 करोड़ का निवेश, जो महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा।
- **स्व–सहायता समूह (एसएचजी):** 1 मिलियन से अधिक एसएचजी का गठन किया गया है, जिनका संचयी ऋण वितरण 46,900 करोड़ तक पहुंच गया है, जिससे महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला है।

आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार

आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार के तहत राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है साथ ही पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे राजनीतिक क्षेत्र में उनका योगदान और भागीदारी बढ़ी है। महिला आरक्षण नीति के तहत कुल 108192 महिलाओं को नियमित सरकारी नौकरी मिली है। यह कुल नियमित नियुक्तियों का 47.40 प्रतिशत है। उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी संस्थानों में डिग्री स्तर और उच्च पाठ्यक्रमों में कुल सीटों का 33 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली अविवाहित महिलाओं को प्रति छात्रा 25000 रुपये दिए जाते हैं। इसी तरह स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली अविवाहित छात्राओं को प्रति छात्रा 50000 रुपये दिए जाते हैं।

बीपीएससी और यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए क्रमशः 50 हजार और एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में दक्ष बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात प्लेसमेंट एवं स्वरोजगार का भी प्रावधान है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं को हाउसकीपिंग, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर एवं प्रबंधन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, जो चयनित प्रशिक्षु को बिहार कौशल विकास मिशन के सूचीबद्ध संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क दिया जाता है।[7] महिला एवं बाल विकास निगम ने शेविंग मशीन ऑपरेटर, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, बार बेंडर आदि परम्परागत एवं आधुनिक पाठ्यक्रमों का संयोजन प्रारंभ किया है। डब्ल्यूसीडीसी समाज कल्याण विभाग द्वारा चयनित 37 रोजगार नियमों के तहत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कृषि जैसे अधिकाधिक पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की योजना बना रहा है।

नीतीश कुमार की नई सरकार ने बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनेक काम किया। एनडीए सरकार ने शहर में मनोरंजन क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण और समर्थन जुटाया है। चीन और अमेरिका पहले से ही पटना में तेजी से कारोबार कर रहे हैं। सरकार दो परियोजनाओं पर 300 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है एक पटना में दिल्ली हाट की नकल करने के लिए और दूसरी बुद्ध पार्क बनाने के लिए। नवंबर 2005 के बाद, बिहार सरकार ने कई कानून पेश किए हैं, जिनसे उसे उम्मीद है कि राज्य के उद्योगों के भविष्य के विकास में सकारात्मक योगदान मिला है।

पूंजी निवेश के 300 प्रतिशत की सीमा के साथ 10 वर्षों की अवधि के लिए जमा राशि का 80 प्रतिशत (VAT) प्रतिपूर्ति, शून्य वैट मामलों में भी प्रोत्साहन के लिए प्रावधान, कैप्टिव बिजली उत्पादन के लिए संयंत्र और मशीनरी

पर खर्च की गई राशि का 50 प्रतिशत मौजूदा इकाइयों के लिए वैट प्रतिपूर्ति का 25 प्रतिशत नई इकाइयों के लिए बिजली शुल्क से छूट, भूमि हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क से छूट, औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक पार्क आदि में भूमिध्शेड पर प्रोत्साहन दिया गया। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क आदि में भूमि/शेड पर प्रोत्साहन दिया गया। बीमार और बंद इकाइयों के लिए कॉर्पस फंड का निर्माण एवं वार्षिक न्यूनतम गारंटी/मासिक न्यूनतम गारंटी से छूट और छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए जीसीएसटी घटाकर केवल 1 प्रतिशत कर दिया गया। बिहार पहला राज्य था जिसने 2020 में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन सईद के नेतृत्व में अपनी इथेनॉल नीति बनाई, जिससे इथेनॉल क्षेत्र में 35,000 करोड़ का निवेश हुआ है।[8]

इसके अलावा बिहार सरकार अनेक परियोजनाओं पर कार्य कर रही है जिनमें मुख्य रूप से शहरी विकास, मानव विकास, बैंकिंग संस्थानों में सुधार, कृषि क्रेडिट कार्ड योजना इत्यादि शामिल हैं। बिहार ने 4 मई से 15 मई 2025 तक पांच शहरों में खेलो इंडिया युवा खेलों का 7वां संस्करण आयोजित किया, जो राज्य में खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

निष्कर्ष

इस तरह से विकास के पहलू बिहार की आर्थिक वृद्धि, अवसंरचना संवर्धन और सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं, जो राज्य को एक अधिक समृद्ध भविष्य के लिए भी तैयार करते हैं फिर भी एक तरह से बिहार में विकास के गति को बहुत ज्यादा नहीं कहा सकता है, क्योंकि कई समाजिक मुद्दे पहले जैसे ही है और शिक्षा में कुछ व्यापक बदलाव नहीं हुआ हैं ऐसे में आर्थिक विकास की सीढ़ी को बहुत ही दूर जाना है। कई बंद उद्योगों को फिर से शुरू करने की जरूरत हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए कुछ प्रयास जरूर किये है। बिहार में कई प्रमुख उद्योगों में कृषि, कपड़ा, और खनिज उद्योगों में अपार संभावनाएं हैं। इसके बावजूद बिहार एक गरीब राज्य की श्रेणी में ही आता है। बिहार से लाखों की संख्या में मजदूर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों पर आश्रित हैं जो कि उस राज्य की आर्थिक स्तिथी को भी मजबूत करते हैं। इसी तरह से शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बिहार में ज्यादा हैं और रोजगार, व्यवसाय की तलाश में पलायन करते हैं। भारतीय सन्दर्भ में बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया जाता रहा है, जिसके कई कारण रहे है परन्तु वर्तमान आर्थिक समाजिक विकास के बिभिन्न आयामों पर चर्चा करते हुए यह सामने आता है कि विकास के वास्तविक स्थिति प्रगति की ओर अग्रसर है जो कि एक सफल आर्थिक नीतियों के परिणाम भी कहा जा सकता हैं। यहां के लोगों में काफी संभावनाएं हैं जो की विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सन्दर्भ सूची

1. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/bihars, Accessed on 28/02/2025.
2. The Times of India, 3 January, 2010
3. Patna best city to start businesses: World Bank, The Times of India, New Delhi, 30 June, 2009
4. Economic Survey, 2024-25, Government of Bihar, Finance Department, state.bihar.gov.in, Accessed on 28/02/2025.
5. https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html, Accessed on 01/02/2025.
6. Economic Survey, 2024-25, Government of Bihar, Finance Department, state.bihar.gov.in, Accessed on 01/02/2025.
7. Mehta, B.S. (2012) *Women's Work Participation in Bihar,* Institute for Human Development, New Delhi.
8. Bihar Budget 2019–20, Finance Department, Govt. of Bihar
9. Economic Survey Report: Bihar me Mistri Majdoor Sabse Adhik Kamgar.
10. Prabhat Khabar, 7 November, Ranchi, 2023

****